



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 402) पटना, मंगलवार, 16 मई 2017

सं0 08/आरोप-01-99/2015,सां0प्र0-16948

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

21 दिसम्बर 2016

श्री रामदेव प्रसाद श्रीवास्तव, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-767/99, के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिनारा (रोहतास) के पद पर पदस्थापन के दौरान वृद्धावस्था पेंशन की राशि के गबन करने के आरोपों पर निगरानी थाना कांड सं०-06/88 दर्ज हुआ तथा विधि विभाग के आदेश सं०-एस०पी०-90/91/4303, दिनांक 24.08.1991 द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी गयी। मामले की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय आदेश सं०-15022, दिनांक 07.11.1991 द्वारा निलंबित किया गया। कालान्तर में विभागीय आदेश सं०-10413, दिनांक 20.09.1996 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। उपर्युक्त आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10983, दिनांक 05.10.1996 द्वारा श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री श्रीवास्तव के दिनांक 28.02.2005 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3463, दिनांक 08.03.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पूरित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-1272, दिनांक 25.08.2015) की प्रति संलग्न करते हुए श्री श्रीवास्तव से द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभिकथन की माँग की गयी। इस क्रम में श्री श्रीवास्तव ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-14, दिनांक 15.02.2016) समर्पित किया तथा आरोप का प्रतिकार किया।

आरोप प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपित पदाधिकारी ने राशि का भुगतान स्वयं नहीं किया था बल्कि उन्होंने इस हेतु आदेश दिया था। दिनांक 02.10.1986 को प्रखंड शिविर में इन्दिरा आवास का वितरण वरीय पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। भुगतान का सत्यापन एवं लाभुकों की पहचान पंचायत सचिव ने की थी। जिला पदाधिकारी द्वारा की गयी जाँच में पेंशनधारियों के भुगतान में अनियमितता नहीं पायी गयी। उक्त भुगतान करने वाले नाजिर पर भी कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, जिसके कारण वे आरोप मुक्त हुए। निगरानी थाना कांड सं०-688 से उद्भूत विशेष निगरानी वाद सं०-15/88 में संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2016 को आदेश पारित किया गया। जिसमें श्री श्रीवास्तव एवं अन्य सभी अभियुक्त आरोप मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही/आरोप के इस मामले को संचिकास्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

श्री श्रीवास्तव के निलंबन अवधि (दिनांक 07.11.1991 से दिनांक 30.09.1996 तक) को पूर्ण वेतन की अनुमान्यता के साथ सेवावधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 402-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>